

‘आप आए, सदन में बैठे और मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद’

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपना भाषण समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक वरिष्ठ नेता के स्तर के अनुकूल भाषण दिया।

उत्तम भाषण में जहाँ राष्ट्रपति के संबोधन की आलोचना निहित थी, वहीं उसमें इसके कारण भी दिये थे कि राष्ट्रपति संबंधित अवसर के स्तर तक क्यों नहीं पहुँच पायीं। ऐसा करने के बजाय, उन्होंने वही अलंकृत भाषण दिया, जो वे साल-दर-साल देती आ रही हैं।

राहुल गांधी ने सिर्फ आलोचना ही नहीं की, उन्होंने सरकार को एक वैकल्पिक सोच भी दी कि भारत को वैश्विक ताकतों की परिधि में कैसे लाया जा सकता है, भारत को निर्माण एवं उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रूप कैसे दिया जा सकता है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा एवं बैटरीज के क्षेत्र में चीन के आधिपत्य का सामना कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को जोड़ना, रोजगार पैदा करना तथा उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना की

■ राहुल गांधी का भाषण अधिकांशतः बेहद शांत और धीर-गंभीर था। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों की कटाक्षपूर्ण भाषाशैली से दूरी बनाते हुए मंजे हुए राजनेता की तरह अपनी बात कही।

■ वर्ष 2004 में राहुल ने पहली बार चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था और सांसद बने थे। यह बात यकीन से कही जा सकती है कि उन्होंने एक लम्बा सफर तय किया है।

■ उन्होंने तेलंगाना की जातिगत जनगणना का हवाला दिया और बताया कि वहाँ 90 प्रतिशत लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यक हैं। शेष भारत की भी यही स्थिति है। दुर्भाग्य की बात है कि उनकी सिस्टम में हिस्सेदारी नहीं है और सम्पदा के सृजन और उपभोग का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है।

जातिगत जनगणना दर्शा रही है कि 90 प्रतिशत लोग ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं और अगर शेष भारत की भी यही स्थिति है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के तंत्र में उनकी दवावदारी नहीं है तथा वे घन के सृजन और उसे उपभोग से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नये मतदाता जुड़े थे और इनमें से अधिकांश मतदाता उन्हीं चुनाव क्षेत्रों में जुड़े थे, जहाँ भाजपा जीती है। उन्होंने कहा कि मात्र एक बिल्डिंग में ही, 7,000 नये मतदाता जुड़े थे तथा बार-बार किये गये अनुरोधों

के बावजूद, चुनाव आयोग इन नये मतदाताओं के नाम तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के नाम तथा अन्य डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा था, जिसकी वे माँग कर रहे थे।

राहुल ने जानना चाहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग के चयन के लिए निर्धारित चयन समिति से क्यों हटा दिया गया। अब समिति में मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी हैं। उन्होंने जानना चाहा कि चयन समिति में उनकी (राहुल) भूमिका क्या होगी।

राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुये, यह जानना चाहा कि ट्रंप के राज्याभिषेक में मोदी को आमंत्रित किये जाने की अनुनय-विनय करने के लिये विदेश मंत्री कई बार अमेरिका क्यों भेजे गये। उन्होंने कहा कि अगर भारत मजबूत होता तो मोदी को आमंत्रित करने के लिये ट्रंप स्वयं आते।

राहुल गांधी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी इस बात से इनकार कर चुके हैं कि चीनी लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं तथा जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने कहा कि थल सेनाध्यक्ष ने इस बात का खंडन किया और कहा था कि चीनी लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अदालत ने बच्चों की कस्टडी, दादा-दादी से लेकर माँ को सौंपी

जयपुर, 3 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना निगरानी बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर गंभीरता दिखाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 11 साल की बच्ची और उसके सात साल के भाई की कस्टडी दादा-दादी से लेकर उनकी माँ को सौंप दी है। हालाँकि अदालत ने दादा-दादी को हर रविवार दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे तक बच्चों से मिलने की छूट दी है। बच्चे पिता की मौत के बाद अपने दादा-दादी के पास रह रहे थे। अदालत

■ हाई कोर्ट ने कहा कि दादा-दादी की जानकारी से 11 साल की बच्ची वीडियो बनाकर यू-ट्यूब पर अपलोड करती थी, जो अनुचित है।

ने कहा कि बच्ची वीडियो बनाने के बाद उसे एडिट कर यूट्यूब पर अपलोड कर रही है और उसके दादा-दादी को वीडियो अपलोड होने की जानकारी भी है, लेकिन वे उस पर निगरानी को लेकर उदासीन रहे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश बच्चों की माँ की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में कहा गया कि उसके पति की किडनी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इस दौरान, याचिकाकर्ता के किडनी नहीं देने और उसकी नन्द के किडनी देने पर उसके सास-ससुर गलत व्यवहार करते थे। उन्होंने बच्चों को अपने पास रखकर याचिकाकर्ता को घर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने कैनडा व मैक्सिको पर 25 प्रतिशत और चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया

टैरिफ में वृद्धि से ऑटो मोबाइल से लेकर तेल उत्पादन कम्पनियों पर विपरीत प्रभाव की आशंका से शेयर बाज़ार गिर गया

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। अपने वादे के अनुसार, डॉनल्ड ट्रंप ने एक विशाल आर्थिक युद्ध की पहली तोप चला दी है। उन्होंने कैनडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत टैरिफ और चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इसके विपरीत, प्रसिद्ध समाचार संस्था सी.एन.एन. द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि अधिकतर लोग इन टैरिफ का अत्यधिक विरोध कर रहे हैं।

संख्या बहुत बड़ी है। टैक्स एजेंसियों के अनुसार, ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ 1.4 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के सामान को प्रभावित करेंगे, तुलना के लिए, यह भारत के जीडीपी का लगभग एक तिहाई है।

व्यापक आर्थिक प्रभाव फैल रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स गिर गए हैं, क्योंकि ऑटो मोबाइल से लेकर तेल उत्पादन जैसी संसाधन कंपनियों तक पर इसके प्रतिकूल असर की आशंका है। उदाहरण के लिए, टैरिफ से बचने के लिए, भारत ने कथित रूप से मोटरसाइकिल्स पर ड्यूटी घटा दी है। ट्रंप ने हाई-एंड हर्ले

■ टैरिफ से बचने के लिए भारत ने अमेरिकन मोटर साइकिल हार्ले डेविडसन पर पहले ही शुल्क घटा दिया है। असल में ट्रम्प ने शिकायत की थी कि भारत में टैक्स ज्यादा होने की वजह से हार्ले डेविडसन मोटर साइकिल का आयात नहीं हो रहा है।

■ मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ने से जापानी कार निर्यात प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को निर्यात करने के लिए जापानी कम्पनियां मैक्सिको में कारें बना रही हैं।

■ टैक्स एजेंसियों के अनुसार, टैरिफ बढ़ाने की ट्रम्प की घोषणा से 1.4 ट्रिलियन डॉलर का सामान (गुड्स) प्रभावित होगा।

डेविडसन मोटरसाइकिल्स के प्रवेश को नुकसान पहुँचाने वाले टैरिफ पर शिकायत की थी।

ट्रंप द्वारा किए गए पहले घमाके से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप ने चीन के खिलाफ अपना रुख थोड़ा नरम कर दिया है, जबकि अपने निकटतम पड़ोसियों के खिलाफ वे अधिक ताकत दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि

चीन, अमेरिका के पड़ोसियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है और चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमेरिका में उल्टा असर हो सकता है।

ब्लूमबर्ग की कुछ आंतरिक गणनाओं के अनुसार, वर्तमान स्तरों पर, चीन पर अमेरिकी टैरिफ इसके जीडीपी को लगभग 1 प्रतिशत नुकसान पहुँचा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक भाजपा प्रमुख विजयेन्द्र के आत्मविश्वास का राज़ क्या है

वी.वाय. विजयेन्द्र ने दावे से कहा, कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास ही रहेगा

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाय. विजयेन्द्र जो कि पूर्व मुख्यमंत्री व कर्नाटक लिंगायत नेता बी.एस. येदियुरप्पा के पुत्र हैं, के खिलाफ विद्रोह पनप रहा है पर उन्हें पूरा यकीन है कि इस लड़ाई में वे ही जीतेंगे और पार्टी के प्रमुख बने रहेंगे।

विजयेन्द्र ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान अन्य राज्यों के चुनावों पर केन्द्रित है, इसके बाद जल्दी ही विवाद सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने शिवमोगा में पत्रकारों से बात की तथा कहा कि पार्टी के आन्तरिक मतभेदों को सार्वजनिक रूप से उछालने का पार्टी को

■ विजयेन्द्र कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक लिंगायत नेता बी.एस. येदियुरप्पा के पुत्र हैं, उन्हें एक साल पहले ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था।

■ विजयेन्द्र को अपनी कार्यशैली व कई अन्य कारणों से वरिष्ठ नेताओं का विरोध सहना पड़ रहा है, पर, वे इसके प्रति बेफ्रिक नज़र आ रहे हैं। शिवमोगा में पत्रकारों से वार्ता में भी वे आत्मविश्वास से पूर्ण नज़र आए।

भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और बेहतर होगा कि अगर कभी अपने मतभेद पार्टी मंच पर दर्शाए। उन्होंने कहा, सभी मसले हफ्ते दस दिन में सुलझा लिए जाएंगे। पार्टी आलाकमान की हर घटना पर पैनी नज़र है। विजयेन्द्र को एक साल पहले

पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और काफी अरसे से उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विरोध सहना पड़ रहा है और उनकी कार्यशैली से भी लोग नाराज़ हो रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूटान नरेश महाकुंभ में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे

लखनऊ, 3 फरवरी। महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी में आस्था को डुबकी लगाने की चाहत के साथ, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक सोमवार को लखनऊ पहुंचे। वांग्चुक मंगलवार को प्रयागराज जाकर संगम में स्नान करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल

■ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भूटान नरेश को पुष्पच्छ प्रदान कर उनका कुशलक्षेम जाना। भूटान नरेश ने भी योगी का अभिवादन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने की अपील खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने

सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, याचिका “इल कन्सीड”, हम ऐसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति के सचिव तथा अन्य को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल को उनके पद से तुरन्त ही वापस बुलाया जाये। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति संजय कुमार की बैंच ने कहा कि न्यायापालिका भी संविधान के प्रावधानों से बंधी हुई है। बैंच ने याचिका में किये गये अनुरोध को “कुविचारित” (इल. कन्सीड) बताया।

बैंच ने कहा, “हम ऐसी प्रार्थनाओं पर स्वीकृति नहीं दे सकते। इसके (राज्यपाल को हटाया जाना) लिये

■ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान में को राज्यपाल हटाए जाने संबंधी प्रावधान हैं, हम खुद संविधान से बंधे हैं।

■ तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को वापस बुलाने का निर्देश देने के संबंध में वकील सी.आर. जयासुकिन ने यह याचिका दायर की थी।

■ याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल राजनीति में लिप्त हैं, जबकि संविधान के अनुसार, राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए।

संवैधानिक प्रावधान हैं। अदालत भी संविधान के अधीन है। याचिका खारिज की जाती है।” संविधान के तहत, कोई भी राज्यपाल “राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान अपना पद ग्रहण करता है तथा

अगर “राष्ट्रपति की प्रसन्नता बने रहने पर”, अपने पद पर पाँच वर्ष के कार्यकाल तक के लिये रह सकता है। याचिकाकर्ता एडवोकेट सी.आर. जया सुकिन ने व्यक्तिशः कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की एक

शृंखला में कहा गया है कि राज्यपाल राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता तथा संविधान में निहित कार्यों को ही कर सकता है।

याचिका में आगे कहा गया, “इस स्थिति में, राज्यपाल को संविधान द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों तक ही सीमित रहना चाहिये। उसे ऐसी कोई शक्ति काम में नहीं लेनी चाहिये, जो संविधान या उसके तहत बने कानून द्वारा उसे नहीं दी गई है।”

6 जनवरी को तमिलनाडु के राज्यपाल, सदन में राष्ट्रगान न बजाये जाने के विरोध में, बैठक शुरू होने के तुरन्त बाद राज्य विधानसभा से चले गये थे।

राज भवन के अनुसार, “राज्यपाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल -प्रियंका ने दिल्ली में रोड शो किया

नयी दिल्ली, 03 फरवरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज कालकाजी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

गांधी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी में आयोजित रोड शो में क्षेत्र के लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लाम्बा को वोट देने की अपील

■ दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी के कालकाजी तथा प्रियंका के कस्तूरबा नगर में हुए रोड शो में अच्छी भीड़ थी।

को। इस रोड शो में उनके साथ पार्टी प्रत्याशी अलका लाम्बा भी थीं। उन्होंने किफ दिल्ली का प्यार और विश्वास सिर्फ कांग्रेस के साथ है। हमने किया था, फिर कर दिखाएंगे, दिल्ली की खुशहाली वापस लेकर आएंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार सह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर टैरिफ लगाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी जोरदार निंदा की है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि चीन इन एकतरफा कदमों का विरोध करता है और अपनी वैध अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए जवाबी उपाय अपनाएगा।

चीन ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वह फेंटेनल संकट का समाधान निष्पक्षता और तर्कसंगत तरीके से करें, न कि टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाए। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अतिरिक्त शुल्क उल्टा असर डाल सकते हैं और डूंग नियंत्रण पर भविष्य के सहयोगी प्रयासों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अमेरिका से यह भी कहा गया कि वह

अपनी भ्रामक प्रतिक्रियाओं को सुधारे, मादक पदार्थों के खिलाफ सहयोग में जो सकारात्मक गति प्राप्त की गई है, उसे बनाए रखें और स्थिर और स्वस्थ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दें। दर्द निवारक और जल्दी से लत बनने वाले सिंथेटिक ओपिओइड्स, जिनमें फेंटेनल भी शामिल है, लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार-बार चीन की आलोचना की है, उस पर फेंटेनल -संबंधित पदार्थों के मुख्य स्रोत होने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में, चीन ने लगातार यह कहा है कि दुनिया के सबसे सख्त डूंग नियंत्रण प्रणालियों में से एक चीन में लागू है, और मादक पदार्थों के प्रवर्तन पर अमेरिका के साथ व्यापक सहयोग करता है।

चीन की सरकार ने टैरिफ्स को

■ चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने अमेरिका द्वारा की गई टैरिफ वृद्धि की आलोचना की तथा इसे आधारहीन व ड्रग्स नियंत्रण सहयोग के लिए नुकसानदेह बताया।

■ उक्त प्रवक्ता ने कहा कि समस्या का मूल कारण यह है कि अमेरिका में फेंटेनल की मांग बहुत ज्यादा है और इस मुद्दे पर वहाँ की कानून व्यवस्था लचर है।

फेंटेनल से जोड़ने के किसी भी प्रयास को नकारते हुए कहा है कि ऐसे लिंक जोड़ना अन्यायपूर्ण है और डूंग नियंत्रण में सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए हानिकारक है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि व्यापार और टैरिफ विवादों से किसी को कोई लाभ नहीं होता और अमेरिका से आग्रह किया कि वह फेंटेनल संकट का समाधान निष्पक्षता वृष्टिकोण से करें, न कि टैरिफ दबावों का उपयोग करें।

विदेश मंत्रालय ने चीन के मानवीय प्रयासों का हवाला दिया, जिसमें उसने अमेरिका फेंटेनल संकट से निपटने में मदद की थी। वर्ष 2019 में, वाशिंगटन के अनुरोध पर, सभी फेंटेनल संबंधित पदार्थों को नियंत्रित दवाओं के रूप में वर्गीकृत करने वाला चीन पहला देश बन गया था। मंत्रालय ने यह दावा किया कि इस नियामक बदलाव के बाद, अमेरिका

को चीन से फेंटेनल संबंधित कोई भी पदार्थ भेजे जाने की खबर नहीं मिली है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि चीन के प्रयासों के बाद भी अतिरिक्त टैरिफ्स डूंग नियंत्रण पर भविष्य के सहयोग को कमजोर कर सकते हैं और चीन ने अमेरिका से अपने वृष्टिकोण को सुधारने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन से यह भी कहा कि वह द्विपक्षीय मादक पदार्थों के खिलाफ प्रयासों में प्राप्त सकारात्मक गति को बनाए रखे और स्थिर और रचनात्मक रिश्तों के लिए काम करे।

उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह सामान्य आर्थिक सहयोग को बाधित करते हैं, जबकि अमेरिका के आंतरिक मुद्दों को हल नहीं करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने विवादों को हल करने के लिए समानता और आपसी सम्मान पर आधारित सार्थक संवाद की आवश्यकता की बात की और यह जोर दिया कि सहयोग और संघर्ष से बचने के लिए यह जरूरी है ताकि द्विपक्षीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिल सके।

चीन की राज्य-प्रयोजित शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्टों के अनुसार, इसी बीच अमेरिका के टैरिफ्स के खिलाफ व्यापक रूप से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विरोध दवाओं का है। चीन कार्यसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने शहरी औद्योगिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश

जयपुर, 3 फरवरी। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित कराया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। बिल के प्रावधानों के अनुसार, खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यह

■ इस बिल को इसी सत्र में बहस के बाद पारित कराया जायेगा।

प्रक्रिया अपनाया जरूरी होगा। इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। बिल में लव जिहाद को परिभाषित किया है। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है, वह लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी करता है तो फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है।